JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

हिंद प्रशांत क्षेत्र में सशक्त व दीर्घकालिक भूमिका में दिखता भारत

Sarita Sharma

शोधार्थी

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

SUNRISE UNIVERSITY, ALWAR,RAJASTHAN

शोध सारांश– भारत की नीति हमेशा से ही हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में अधिक से अधिक शांति एवं सौहार्द की रही है तथा इस क्षेत्र को मुक्त, खुले समावेशी क्षेत्र के रूप में विकसित होते रहने देने की रही है। इसके विपरीत चीन अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा, जिन्हें रोकने के लिए अमरीका, भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान स्थायी ढांचा विनिर्माण के वित्त पोषण के लिए कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में पहले अमरीका का दबदबा था परंतु कुछ वर्षो में हुए बदलाव के कारण जिस तरह से चीन द्वारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह, सोलोमन द्वीप से सामरिक समझौता सहित अनेक देशों को ऋण जाल में फंसाने का कुचक्र चलाया जा रहा हैं, उससे इस बात का डर बढ़ गया है कि हिंद–प्रशांत क्षेत्र में चीन प्रभुत्व स्थापित न कर ले।

संकेताक्षर– हिंद–प्रशांत, सामरिक नीति, हिन्द महासागर, हिंद–प्रशांत ।

शोध विस्तार हिंद–प्रशांत क्षेत्र से ही दुनिया भर का 70 से 75 प्रतिशत आयात–निर्यात होता हैं तथा दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाह भी इसी क्षेत्र के हैं। हिंद–प्रशांत क्षेत्र में 38 देश शामिल है तथा विश्व की 60 प्रतिशत जीडीपी का योगदान इसी क्षेत्र से होता हैं। यह क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पाद को लेकर उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के लिए संवेदनशील बना रहता है। भू–आर्थिक प्रतिस्पर्धा का संकेत देती कुछ ऐसी घटनाएं है जिनसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं, बढ़ता सैन्य खर्च तथा प्राकृतिक संसाधनों को लेकर गलाकाट प्रतिस्पर्धा विश्व शांति के लिए खतरा बन सकती हैं।[1]

हिंद–प्रशांत इस क्षेत्र में किसी भी एक देश का प्रभुत्व नहीं चाहता तथा विभिन्न समूहों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि चीन इस क्षेत्र में 'हावी' न हो जाए क्योंकि चीन हिंद–प्रशांत देशों के लिए तो खतरा है ही, भारतीय हितों के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमरीका, जापान के बीच क्वाड का बहुपक्षीय समझौता हिंद–प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन तथा चीन पर दबाव बनाए जाने के दृष्टिगत एक प्रमुख गठजोड़ तो है ही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जापान, पापुआ न्यू गिनी द्वीप, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा हिंद–प्रशांत क्षेत्र में भारत की सशक्त व दीर्घकालिक भूमिका को स्पष्ट करती है।

भारत अब अपनी 1992 की 'लुक ईस्ट' पॉलिसी के स्थान पर चीन के रणनीतिक व सामरिक प्रभाव के प्रतिकार के लिए तैयार है। वह एक शक्ति के रूप में विशाल हिंद–प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कूटनीतिक पहल कर 'लुक ईस्ट' पॉलिसी के परिष्कृत रूप 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी की तरफ कदम बढ़ा चुका हैं।[2]

अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन को भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ पापुआ न्यू गिनी आना था परंतु अमरीका में गंभीर आर्थिक संकट होने से बाइडन ने यह यात्रा रद्द कर दी, जिसका भारत को एक सीधा लाभ यह भी मान सकते हैं कि पापुआ न्यू गिनी में 'फोकस' भारत पर ही रहा। यह लाभ इसलिए भी महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि चीन से मुकाबला करने के लिए यह टापू भले ही छोटा हो, मगर रणनीतिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण है। हालांकि क्वाड का आयोजन ही अपने आप में चीन की घातक महत्त्वाकांक्षाओं को काबू करने का प्रयास है पर अचानक क्वाड का रद्द होना चीन के होसले बुलंद ही करेगा। इस बीच भारत के लिए जरूरी है कि जो भी कुछ बेहतर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से निकल कर आ सके, उसका प्रयोग कर हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति और बेहतर की जाए।

बीजिंग घरेलू और वैश्विक स्तर पर बढ़ती चुनौतियों के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों से कहा हैं कि वे सबसे मुश्किल हालातों और विकट संकट के लिए तैयारी रखें। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की एक बैठक को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जिन मुद्दों का हम अब तक सामना करते आए हैं उनकी जटिलता और दुश्वारियां अब पहले से कहीं बहुत अधिक हैं। जिनपिंग ने कहा कि हमें 'बॉटम लाइन' दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ना होगा। सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को अपने गवर्नेस मॉडल को केंद्रीय पहलू बनाने वाले जिनपिंग की तरफ से युद्ध के लिए तैयार रहने की ये सबसे ताजी और सख्त चेतावनी है।[3]

चीन और अमरीका के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में चीन ने अमरीकी रक्षामंत्री के ओर से सैन्य वार्ता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। चीन ने कहा है कि दोनों देशों के रक्षामंत्रियों बीच बैठक की कोई

संभावना नहीं है। चीन का बयान दोनों देशों के रक्षा मंत्री सिंगापुर में एक सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि वाशिंगटन को चीन की संप्रभुता और सुरक्षा चिंताओं का ईमानदारी से सम्मान करना चाहिए। गलती को तुरंत ठीक करना चाहिए। ईमानदारी दिखाते हुए दोनों सेनाओं के बीच बातचीत और संचार के लिए आवश्यक माहौल बनाना चाहिए।

ईयू के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेप बोरेल ने कहा, यूरोपीय संघ हिंद प्रशांत क्षेत्र में जलविद्युत, सौर ऊर्जा संयंत्रों को लेकर परिवहन, बुनियादी ढांचे, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक में निवेश करेगा। बोरेल ने कहा हम 20 ग्लोबल गेटवे परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। बोरेल ने जोर देकर कहा कि ईयू के विदेश मंत्रियों ने चीन पर आर्थिक निर्भरता को कम करने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का रोड मैप पेश किया है। इसे कैसे लागू किया जाए, इस पर विचार हो रहा है।[4]

समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाएंगे :– बैठक के दौरान फ्रांसीसी विदेश मंत्री कैथरीन कॉलोना ने कहा कि हम एक स्वतंत्र, मुक्त, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र देखना चाहते हैं। इसके लिए अपने सभी समकक्ष देश से सहयोग में विस्तार देख रहे है। उन्होंने कहा, हम यूरोप को एक खेमे में नही देख रहे। खेमेबाजी से विवाद और टकराव बढ़ता है। भारत के विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कॉलोना से यहां मुलाकात की है। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे की परेड में शामिल होंगे।

चीन–रूस का नो लिमिट करार दुनिया के लिए खतरा :– बैठक में जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने रूस और चीन के बढ़ते सैन्य सहयोग के बारे में चिंता व्यक्त की और कहा कि मॉस्व के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमकता के बाद से यूरोप में सुरक्षा स्थिति को भारत–प्रशांत क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता हैं। उन्होंने कहा कि रूस और चीन का नो–लिमिट करार दुनिया के लिए खतरा है।[5]

करीब आ रहे एशिया में अमरीका के सहयोगी देश :– दक्षिण कोरिया और जापान जैसे पड़ोसी देश दशकों से एक–दूसरे के लिए अजनबी की तरह रहे, परंतु अब वे एक नई साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। अमरीका के कहने पर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विस्तार को लेकर चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये के चलते। दोनों देश अपनी सुरक्षा स्थिति को लेकर पुनर्विचार कर रहे हैं। अमरीका के एशियाई सहयोगी प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते संकट पर स्पष्ट राय व्यक्त कर रहे है, और अमरीका को इसे सुनना चाहिए।

अमरीकी राजनीतिक विश्लेषक केवल बीजिंग के साथ जारी गतिरोध पर फोकस कर रहे है और जापान–दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ती नजदीकियों पर उनका ध्यान नहीं गया। चीनी विदेश मंत्री चेता चुके है कि जब तक अमरीका प्रतिद्वंद्वि रणनीति से पीछे नहीं हटेगा तब तक 'संघर्ष और आमना–सामना' होता

रहेगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आरोप है कि चीन की आर्थिक परेशानियों की वजह है –अमरीका की 'नियंत्रण, घेरेबंदी और दबाव की नीति।' दूसरी ओर, इन दिनों चीन–अमेरीका संबंध खराब होने के लिए अमरीका को दोषी करार देना अमरीका में एक फैशन–सा बन गया है। कुछ लोग वाशिंगटन में 'सामूहिक सोच' के राजनीतिकरण को अमरीका के आक्रामक रूख की वजह होने का दावा कर रहे हैं और चीन ऐसे दावों का लाभ उठाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने रूतबे में आई गिरावट की वजह अमरीका को बता रहा हैं। चीन का प्रचार तंत्र दक्षिण कोरिया व जापान के बीच सहयोग बढ़ने के लिए भी अमरीका को जिम्मेदार ठहरा रहा है और उसका आरोप है कि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल अमरीका की कठपुतली हैं। वास्तविकता यह है कि इस नए सहयोग में वाशिंगटन का कोई हाथ नहीं है। हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसकी प्रशंसा अवश्य की हैं।[6]

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने पहल करते हुए कहा कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जापान की बंधुआ मजदूरी प्रथा के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए दक्षिण कोरिया फंडिंग करेगा। प्रतिक्रियास्वरूप जापानी प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा ने द.कोरिया के साथ संबंध प्रगाढ़ करने की बात कही है। इसके साथ ही जापान इंटेलिजेंस साझा करने से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तक सब क्षेत्रों में सहयोग के लिए तैयार हो गया। जापान इस सप्ताह और मई में हिरोशिमा में होने वाली जी–7 राष्ट्रध्यक्षों की बैठक में यून को आमंत्रित करेगा। अप्रैल में बाइडन भी यून को स्टेट डिनर के लिए आमंत्रित करेंगे। दरअसल, अमेरीकी नीति निर्माता एशिया को केवल अमरीका–चीन द्विपक्षीय संबंधों के नजरिये से देखते हैं। लेकिन द.कोरिया और जापान के ये कदम बताते हैं कि क्षेत्र में तनाव की वजह चीन का व्यवहार है, अमरीका की आक्रामक नीति नहीं।[7]

जापान अगले पांच सालों में अपना रक्षा खर्च दोगुना करने वाला हैं। द.कोरिया अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए चीनी बाजार और आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम कर रहा हैं। दोनों ही देश चीन के साथ तनाव प्रबंधन चाहते है और वे महसूस कर रहे हैं कि क्षेत्रीय सुरक्षा को चीन से मिल रही चुनौती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एशियाई सहयोगी क्षेत्र में अमरीका की अधिक सक्रियता चाहते है, चीन की नहीं। वे समझ चुके हैं कि समान विचारधारा वाले देशों को साथ मिलकर काम करने पर अधिक समय देना चाहिए न कि चीन और प्योंगयांग के नेताओं को राजी रखने पर। अमरीका को अपने एशियाई सहयोगियों को आश्वस्त करना होगा कि अमरीका क्षेत्र के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, और ऐसा सिर्फ सैन्य तौर पर नहीं।

एशिया में अमरीकी आर्थिक निवेश रणनीति महत्त्वपूर्ण है, पर क्षेत्रीय नेता पाते है कि बाइडन प्रशासन की व्यापार रणनीति ज्यादा असर नहीं छोड़ रही है। रिपब्लिकन नेता राजा कृष्णमूर्ति के अनुसार, 'हम चीन के साथ कोई युद्ध नहीं चाहते .....हम शांति चाहते है। पर उस शांति को पाने के लिए हमें आक्रामकता से

मुक्ति पानी होगी।' एशिया में अग्रिम पंक्ति के अमरीकी सहयोगी संकेत भेज रहे हैं, जरूरत है कि अमरीका मदद के लिए उनकी ओर कदम बढ़ाए।

अमरीका और ताइवान में इस समय दांव पर लगे सिद्धांतों के बारे बहस नहीं हो रही है। अमरीकी सांसदों को ताइवान यात्रा का अधिकार है और ताइवान को उनकी मेजबानी का, जिसके लिए उसे कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। परंतु एक व्यवहारगत वास्तविकता है, जिसका सामना पेलोसी को नहीं बल्कि ताइवानी जनता को करना पड़ेगा। ऐसे में बाइडन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह ताइवान की मदद करे। इस यात्रा से उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, वह यह कि चीन ने इस पर जो अनावश्यक प्रतिक्रिया जताई है, संभव है ताइवान व अन्य देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की तैयारी करे।[8]

समय के साथ दुनिया में चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर अमरीका रक्षा विभाग की रिपोर्ट के खुलासों के बीच चीन के जासूसी पोत की हिंद महासागर में मौजूदगी ने हलचल मचा दी है। बीस हजार टन वजनी जासूसी जहाज युआन वांग–5 गत सोमवाद को इंडोनेशिया के सुंदा स्ट्रेट से हिंद महासागर में प्रवेश किया है। यह खबर ऐसे समय में आई है, जब भारत ने उड़ीसा के बालासोर स्थित अब्दुल कलाम प्लेटफॉर्म से मिसाइल परीक्षण के लिए बंगाल की खाड़ी में 15–16 दिसंबर को नो फ्लाइंग जोन के लिए नोटा में (नोटिस टू एयर मैन) जारी कर रखा हैं। इस दौरान 5000 किलोमीटर क्षमता वाली अग्नि–5 मिसाइल को स्ट्रेटजिक फोर्सेज कमांड (एसएफसी) में शामिल करने से पहले का परीक्षण प्रस्तावित हैं। मिसाइल के फेज थ्री का यूजर ट्रायल गत अक्टूबर में किया गया था। चीन का उत्तरी इलाका भी इस मिसाइल की जद में आता है।

अब यह स्थापित तथ्य है कि फरवरी में यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण उभरी वैश्विक व्यवस्था में अमरीका, चीन और रूस के साथ परिसंघ में भारत ने खुद को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर अपनी जगह बनाई हैं। भारत ने दृढ़तापूर्वक अपनी तटस्थता को साबित किया है। भारत ने रूस की निंदा करने से इनकार तो किया ही, मास्को पर पश्चिम के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों की परवाह किए बिना रूसी आयात को भी बनाए रखा। एक वक्त तो ऐसा आया जब उसने यूएस को भी नाराज कर दिया था। अमरीका अधिकारियों ने रूसी मुद्दे पर भारत की नितियों को लेकर खतरनाक परिणामों की ओर इशारा भी किया किंतु जल्द ही वाशिंगटन को अहसास हो गया कि भारत को उसके द्वारा निर्धारित नक्शे–कदमों पर चलने को मजबूर नहीं किया जा सकता। भारत के सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण का साक्षी बना टोक्यो में पिछले माह हुआ क्वाड सम्मेलन, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडन ने समिट से इतर बातचीत की।[9]

चीन भी इसे मानता है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में जहां भारत को पश्चिम समेत जर्मनी, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस जैसे देशों द्वारा लुभाया जा रहा है, वह दिल्ली के साथ सभी संबंधों को तोड़ नहीं सकता है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने संबंधों को बढ़ाने की ओर इशारा करते हुए कहा है कि दोनों देश प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, वे 'परिपक्क पड़ोसियों' के रूप में एक–दूसरे के लिए पूरक की भूमिका निभा सकते है। उन्होंने कहा, 'उन्होंने उत्सुकता को महसूस किया है कि दोनों पक्ष इस आम राय को मानने के लिए सहमत हैं कि वे एक–दूसरे के अवसर बन सकते हैं।'[10]

दूसरा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत जानता है कि वैश्विक मामलों में उसकी बढ़ती भूमिका के मद्देनजर, चीन को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, चीन और भारत दोनों के हित में है कि वे एक–दूसरे की उचित समझ के साथ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सीमा मुद्दे को संबोधित करें। तीसरा, चीन के साथ भारत के संबंधों से दुनिया को एक ताकतवर संदेश भी जाएगा कि भारत के पास अपने पड़ोसियों से संबंधों को निभाने, मजबूती देने की सामर्थ्य और क्षमता है। इससे पश्चिम को भी क्षेत्र से दूर रहने का बोध होगा। रणनीतिक रूप से पाकिस्तान को भी यह बताने में मदद मिलेगी कि इस्लामाबाद मदद और कर्ज के लिए जहां चीन पर निर्भर है, वहीं भारत व बिजिंग के रिश्ते भी बराबरी के धरातल पर है। यह महत्त्वपूर्ण रणनीतिक कदम हैं।[11]

निष्कर्ष– दरअसल, भारत ने यह साफ कर दिया कि चीन के साथ कड़वे मतभेदों के बावजूद, विशेषकर पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के मद्देनजर, वह अपने समग्र हितों में बीजिंग के साथ रिश्ते बनाने के खिलाफ नहीं है। हालांकि, भारत जोर देता रहा है कि चीन को लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बहाल करनी चाहिए, लेकिन भारत ने बहुल स्पष्टता से यह भी कहा कि वह अपने हितों के अनुकूल चलेगा और चीन के साथ अपने संबंधों को उस तरह संचालित नहीं करेगा, जैसा पश्चिम चाहता है। भारत तीन बड़े परिदृश्यों पर नजर रख रहा है। पहला–बीजिंग के साथ सीमा तनाव को द्विपक्षीय बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल करना जरूरी है। हालांकि लद्दाख में अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति लक्ष्य को हासिल करने में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली हैं। ज्यादा सार्थक उपलब्धि, जिसे ध्यान में रखना होगा, यह है कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, संघर्ष की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। हिमालयी इलाके में दोनों पक्षों ने रणनीतिक युद्धाभ्यास किया है, लेकिन उन्होंने संघर्ष को टाल दिया है क्योंकि वे मुद्दों को हल करने की दिशा बातचीत को सबसे अच्छा मानते हैं।

संदर्भ सूची–

1. दी न्यूयार्क टाइम्स, 27 जनवरी, 2013
2. दी न्यूयार्क टाइम्स – 7 जनवरी 2015
3. रिर्पोट फ्रॉम दी ज्वाइन कमेटी ऑफ फारेन अफेयर्स ऑन दी इण्डियन ओशन रीजन – 1971, पार्लियामेन्ट्री पेपर न. 258, पृ. 26
4. 'जिन्दुयांग' (हिन्दमहासागर), 16 जुलाई, 2011
5. http://finance. sina.com.cn
6. http://www.chiniil.com.cn/siti1/jsstpjs/2005/05/26/content-213942.htm
7. पेकिंग रिव्यू जून 2018
8. द एशियन ऐज, दिसम्बर 2019
9. हिन्दुस्तान टाईम्स, 8 नवम्बर 2020
10. पीपुल्स डेली 5 अक्टूबर 2021
11. फॉरेन अफेयर्स 23 फरवरी 2022